# विश्व बैंक

**संपर्क-सूत्र:** *दिल्ली में:* गीतांजलि चोपड़ा (91-11) 2461-7241
ई-मेल: gchopra@worldbank.org
*वाशिंगटन में:* करीना मानासेह (202) 473-1729
ई-मेल: kmanasseh@worldbank.org

## विश्व बैंक द्वारा भारत के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम को सहायता

*गांववासियों को सेवाओं और बाज़ारों से जोड़ने के लिए
400 मिलियन अमरीकी डालर की मदद*

**वाशिंगटन, 23 सितम्बर, 2004** — भारत में ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विकास के लिए विश्व बैंक ने आज यहां 400 मिलियन अमरीकी डालर के सहायता पैकेज को स्वीकृति प्रदान की। गांवों में रहने वालों की बाज़ारों व नागरिक सेवाओं तक पहले से अधिक पहुंच बनाना इस परियोजना का उद्देश्य है।

विश्व बैंक के वरिष्ठ परिवहन विशेषज्ञ **पिअर्स विकर्स** ने कहा, ''*भारत के लगभग 200 मिलियन निवासी ऐसी सड़कों से वंचित हैं, जिन्हें हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सके। इसका ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और गांववासियों के अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बनाने के मार्ग रुकावटें पैदा होती हैं, जिनमें से अधिकतर निर्धन हैं ।*''

ग्रामीण इलाकों में सड़कों के अभाव के प्रति भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया गांवों को सड़कों से जोड़ने वाले कार्यक्रम *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना* को *स्पांसर* करके की है। विश्व बैंक द्वारा आज यहां स्वीकृत ग्रामीण सड़क परियोजना उन ऋणों की श्रृंखला में पहली कड़ी है, जो इस क्षेत्र में भारत सरकार को अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम पर अमल करने के लिए दिए जाएंगे।

यह धनराशि उस मौजूदा धनराशि के अलावा है, जो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क के निर्माण व रखरखाव के लिए चार अत्यंत निर्धन राज्यों — हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश — के आधे से अधिक ज़िलों को मुहैया कराई जा रही है। पिअर्स विकर्स ने बताया कि इस परियोजना में बिहार जैसे अन्य निर्धन राज्यों को शामिल करने के लिए वर्तमान परियोजना का विस्तार किया जा सकता है।

इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में परिवहन पर आने वाली लागत में कमी करना और लोगों के आवागमन तथा माल की ढुलाई में तेज़ी लाना है। परियोजना के अन्य लाभ इस प्रकार हैं: जिंसों और कृषि में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की लागत में कमी, अधिक नियमित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन, ज़मीन के मूल्यों में वृद्धि तथा परियोजना के इलाकों को *रि-लोकेट* करने के लिए सेवाएं मुहैया कराने वालों (अध्यापक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यकर्ता, प्रसार स्टाफ और *कमर्शियल वेंडर्स*) को प्रोत्साहन *(इंसेन्टिव्स)*। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहले से बेहतर पहुंच बनाने तथा अन्य संरचनाओं में पहले से अधिक निवेश करने के अलावा, परियोजना से किसानों को अधिक पैदावार तथा अपनी फ़सलों का विविधीकरण करने के अवसर मिलेंगे और इनके लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों के रखरखाव दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

यह परियोजना भारत के संदर्भ में विश्व बैंक की *कंट्री स्ट्रैटेजी* के अनुरूप है, जिसमें ग्रामीण इलाकों के तेज़ी से विकास को देश में निर्धनता दूर करने के मुख्य साधन के रूप में देखा गया है। **पिअर्स विकर्स** ने स्पष्ट किया, *''आशा है कि प्रस्तावित परियोजना से भारत में निर्धनता दूर करने में दो तरीकों से मदद मिलेगी। प्रथम, सड़कों में प्रस्तावित सुधारों से आर्थिक गतिविधियों में अंशदान होगा और इस तरह रोज़गार, कारोबार, विशेषज्ञता प्राप्त करने के अधिक अवसर पैदा होंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। दूसरे, ग्रामीण सड़कों से विशेष रूप से स्वास्थ्य-संबंधी देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं तक पहुंच पहले से बेहतर हो जाएगी तथा परियोजना के अंतर्गत इलाकों में निर्धनों के रहन-सहन में सुधार होगा।''*

विश्व बैंक के भारत-स्थित कंट्री डाइरेक्टर **माइकेल कार्टर** ने कहा है कि यह परियोजना *कंट्री स्ट्रैटेजी* में उल्लिखित तीन महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों — चयनात्मकता, भागीदारी और कार्यक्रम पर आधारित दृष्टिकोण — के आधार पर तैयार की जा रही है। *''वर्तमान योजना के लिए दी जाने वाली सहायता अगले पांच से सात वर्षों के भीतर सभी गांवों को सड़कों से जोड़ देने के सरकार के कार्यक्रम में मदद करने के लिए दिए जाने वाले ऋणों की श्रृंखला की पहली कड़ी है। जहां-जहां व्यावहारिक होगा, परियोजना के काम की योजना तैयार करते हुए क्षेत्रवार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।''*

सहायता-संबंधी पैकेज में *इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवेलपमेंट (आईबीआरडी)* से 100 मिलियन अमरीकी डालर का लोन और *इंटरनेशनल डेवेलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए)* से 300 मिलियन अमरीकी डालर का क्रेडिट शामिल है। *आईडीए* बैंक की लेंडिंग करने वाली संस्था है। *आईबीआरडी* द्वारा दिया जाने वाले लोन का भुगतान 20 वर्ष में करना होगा और पहले पांच वर्ष तक कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जबकि *आईडीए* द्वारा दिया जाने वाले क्रेडिट का भुगतान 35 वर्ष में करना होगा और पहले दस वर्ष तक कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

*भारत में विश्व बैंक की गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए निम्न वेबसाइट देखें:*
*http://www.worldbank.org.in/*

*इस परियोजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए निम्न वेबसाइट देखें:*
*http://www.worldbank.org.lv/external/default/main?pagePK=64027221&piPK=64027220&theSitePK=295584&menuPK=295617&Projectid=PO77977*